

## देवास-एंट्रिक्स डील

### प्रलिस के लयः

एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, एस-बैंड ट्रांसपॉण्डर, इंटरनेशनल टेलीकमयुनिकेशन यूनयिन, आईसीसी, एनसीएलएटी, एनसीएलटी ।

### मेन्स के लयः

संचार प्रणालियों का वकिस ।

## चरचा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष वभिग की वाणजियकि इकाई [एंट्रिक्स](#) और बंगलूरु स्थति स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया के बीच वविदास्पद सौदा एक दशक से अधिक समय से सवालों के घेरे में है ।

HOW IT UNFOLDED		
<p>► <b>Jan 2005:</b> Agreement between Antrix and Devas for former to launch two satellites and lease 90% of S-band to Devas</p> <p>► <b>2011:</b> UPA govt cancels deal on 'security' grounds after allegations of corruption</p> <p>► <b>Aug 2016:</b> CBI charge-sheets former ISRO chief G Madhavan Nair and other officials</p>	<p>► <b>Sept 2017:</b> International Chamber of Commerce awards Devas compensation worth \$1.3 billion</p> <p>► <b>Oct 2020:</b> A United States Federal Court confirms ICC's award</p> <p>► <b>Jan 2021:</b> Govt approaches NCLT to begin liquidation proceedings of Devas. NCLT admits case and appoints liquidator</p> <p>► <b>Sept 2021:</b> NCLAT upholds NCLT order to</p>	<p>liquidate Devas</p> <p>► <b>Dec 2021-Jan 2022:</b> A Canadian court allows seizing of Air India assets by Devas after latter alleges that India breached bilateral treaty with Mauritius. Antrix-Devas deal was signed under this treaty</p> <p>► <b>Jan 2022:</b> Supreme Court upholds NCLT decision, orders liquidation of Devas. Liquidator takes over Devas</p>

## प्रमुख बडि:

- **स्पेक्ट्रम का आवंटन:** अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को एस-बैंड स्पेक्ट्रम 1970 के दशक में प्रदान किया था ।
- **इसरो को स्पेक्ट्रम सौपना:** वर्ष 2003 तक यह संकोच था कयिद इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया तो स्पेक्ट्रम नष्ट हो सकता है ।
  - स्थलीय उपयोग के लयि [दूरसंचार वभिग \(DoT\)](#) को 40 मेगाहर्ट्ज का एस-बैंड दिया गया था ।
  - 70 मेगाहर्ट्ज का अंतरिक्ष वभिग (डीओएस) या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा उपयोग किया जाना था ।
- **संचार प्रणालियों के वकिस के लयि वैश्वकि बातचीत:** प्रारंभ में भारत में संचार प्रणालियों के वकिस हेतु उपग्रह स्पेक्ट्रम के उपयोग के लयि जुलाई 2003 में फोरज (एक यूएस कंसल्टेंसी) और एंट्रिक्स द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कयि गए थे, लेकिन बाद में एक स्टार्टअप की परकिल्पना की गई और देवास मल्टीमीडिया शुरू कयि गया ।
  - इसके बाद देवास मल्टीमीडिया वदिशी नविशकों को आकर्षति करने में सफल रहा ।
- **सौदे पर हस्ताक्षर:** वर्ष 2005 में पट्टे पर एस-बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले मोबाइल उपयोगकर्त्ताओं को मल्टीमीडिया सेवाएँ प्रदान करने के लयि सौदे पर हस्ताक्षर कयि गए ।
  - इस सौदे के तहत इसरो देवास को दो संचार उपग्रह (जीसैट-6 और 6ए) 12 वर्ष के लयि लीज़ पर देगा ।
  - बदले में देवास उपग्रहों पर एस-बैंड ट्रांसपॉण्डर का उपयोग करके भारत में मोबाइल प्लेटफॉर्म को मल्टीमीडिया सेवाएँ प्रदान करेगा ।
  - सौदे के परणामस्वरूप देवास ने पहले जैसी तकनीकों को पेश कर उनका उपयोग कयि ।
- **सौदे को रद्द करना:** इस सौदे को वर्ष 2011 में इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कबिरॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी में घोटाला हुआ है ।
  - यह फेसला 2जी घोटाले के बीच लयिा गया था और आरोप लगाया गया कदिवास सौदे में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के संचार स्पेक्ट्रम को

कुछ समय के लिये सौंपना शामिल है।

○ सरकार ने यह भी माना कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिये एस-बैंड उपग्रह स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है।

- **भ्रष्टाचार के आरोप:** इस बीच अगस्त 2016 में **केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)** ने देवास इसरो और एंटरक्स के अधिकारियों के खिलाफ **"आपराधिक साजिश का पकड़"** होने के लिये सौदे के सम्बन्ध में एक आरोप पत्र दायर किया।
  - इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी. माधवन नायर और एंटरक्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक के. आर. श्रीधरमूर्ति शामिल थे।
- **इंटरनेशनल ट्रेडिंजिगल आर्बिट्रेशन:** देवास मल्टीमीडिया ने इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (ICC) में विलोपन के खिलाफ मध्यस्थता शुरू की।
  - भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय नविश संधि (BIT) के तहत देवास मल्टीमीडिया में मॉरीशस के नविशकों द्वारा और भारत-जर्मनी द्विपक्षीय नविश संधि (BIT) के तहत एक जर्मन कंपनी - ड्यूश टेलीकॉम द्वारा दो अलग-अलग मध्यस्थता भी शुरू की गई थी।
  - भारत को तीनों वविदों में हार का सामना करना पड़ा और नुकसान के तौर पर कुल 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ा।
- **ट्रेडिंजिगल के नरिणय बाद:** भारत सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान नहीं करने के कारण एक फ्रॉंसीसी न्यायालय ने हाल ही में पेरिस में भारत सरकार की संपत्तियों को फ्रॉंज करने का आदेश दिया है, ताकि 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान किया जा सके।
- **भारतीय मध्यस्थता परदिश्य:** हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के वर्ष 2011 के रुख को दोहराया और भारत में देवास मल्टीमीडिया व्यवसाय को बंद करने का नरिदेश दिया।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल कंपनी लॉ अपीलट ट्रेडिंजिगल (NCLAT)** और **नेशनल कंपनी लॉ ट्रेडिंजिगल (NCLT)** के पछिले फैसले को भी बरकरार रखा।
  - एंटरक्स ने जनवरी 2021 में भारत में देवास के परसिमापन के लिये NCLAT में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि इसे एक अनुचित तरीके से नगिमति किया गया था।
  - इन न्यायाधिकरणों ने देवास मल्टीमीडिया को बंद करने का नरिदेश दिया था और इस उद्देश्य के लिये एक अस्थायी परसिमापक नयुक्त किया था।

## वदिशों में भारतीय संपत्तियों की ज़बती

- नयियों के मुताबिक, राज्य और उसकी संपत्तियों अन्य देशों के न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही से सुरक्षित हैं।
  - यह अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है, जिसे 'स्टेट इम्युनिटी' कहा जाता है।
  - इसमें कषेत्राधिकार और नषिपादन दोनों से उन्मुक्त शामिल होती है।
- हालाँकि विभिन्न देशों की कानूनी प्रणालियों से राज्य की सुरक्षा का कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन उपलब्ध नहीं है।
  - इसने एक अंतरराष्ट्रीय शून्यता को जन्म दिया है।
  - नतीजतन, विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय कानूनों और 'स्टेट इम्युनिटी' पर घरेलू न्यायिक प्रथाओं के माध्यम से इस शून्यता को कम करने का प्रयास किया है।
- फ्रॉंस जैसे देश परतबिधात्मक इम्युनिटी की अवधारणा का पालन करते हैं (एक वदिशी राज्य केवल संप्रभु कार्यों के लिये ही परतरिक्षित है) और पूर्ण इम्युनिटी (वदिशी न्यायालय में सभी कानूनी कार्यवाही से समग्र सुरक्षा) के सिद्धांत को नहीं मानते हैं।
- द्विपक्षीय नविश संधि (BIT) के तहत दिये गए नरिणयों के नषिपादन के संदर्भ में इसका तात्पर्य है कि संप्रभु कार्यों (राजनयिक मशिन भवन, केंद्रीय बैंक संपत्तियों, आदि) में संलग्न राज्य संपत्तियों को ज़बत नहीं किया जा सकता है।
- हालाँकि वाणिज्यिक कार्यों में संलग्न संपत्तियों को ज़बत किया जा सकता है।

## S-बैंड स्पेक्ट्रम

- एस-बैंड स्पेक्ट्रम, जो देवास-इसरो सौदे का हिस्सा है, मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिये उपयोग होने के साथ-साथ रुपए के मामले में भी बेहद मूल्यवान है।
- इस आवृत्ति (यानी 2.5 Ghz बैंड) का उपयोग विश्व स्तर पर फोरथ जनरेशन की तकनीकों जैसे वाईमैक्स और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन (LTE) का उपयोग करके मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करने हेतु किया जाता है।
- यह आवृत्ति बैंड अद्वितीय है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में स्पेक्ट्रम (190 मेगाहर्ट्ज) है, जिसे मोबाइल सेवाओं के लिये उपयोग किया जा सकता है।

## द्विपक्षीय नविश संधि

- द्विपक्षीय नविश समझौते से तात्पर्य एक ऐसे समझौते से है जो उन नयियों एवं शर्तों को तय करता है, जिनके तहत किसी एक देश के नागरिक व कंपनियों किसी दूसरे देश में नजि नविश करते हैं। ऐसी अधिकतर संधियों में वविदों की स्थिति में कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ मध्यस्थता का कार्य करती हैं।
- एक-दूसरे के कषेत्रों में हस्ताक्षरकर्ता देश के नागरिकों द्वारा किये गए नजि नविश के प्रचार और संरक्षण के लिये पारस्परिक उपक्रम वाले दो देशों के बीच एक समझौता।
- बीआईटी के एक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवैध राष्ट्रीयकरण और वदिशी संपत्तियों के स्वामित्व व अन्य कार्यों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है जो अन्य हस्ताक्षरकर्ता के राष्ट्रीय स्वामित्व या आर्थिक हितों को कमज़ोर कर सकते हैं।
- बीआईटी में भारत सरकार द्वारा नविशकों के अधिकारों और सरकारी दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों और व्यवहारों के परिप्रेक्ष्य में भारत में वदिशी नविशकों और वदिश में भारतीय नविशकों को समुचित सुरक्षा प्रदान की गई है।

## एंटरक्स कॉर्पोरेशन लमिटिड

- यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के पास है।
- एंटरक्स कॉर्पोरेशन लमिटिड को सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पादों, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा वकिसति प्रौद्योगिकियों के वाणजियकि दोहन व प्रचार प्रसार के लिये सरकार के स्वामित्व वाली एक प्राइवेट लमिटिड कंपनी के रूप में स्थापति कयिा गया था।
- इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष से संबंधति औद्योगिकि कृषमताओं के वकिस को आगे बढाना है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणजियकि एवं वपिणन शाखा के रूप में एंटरक्स पूरे वशिव में अपने अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध करा रही है।

## अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ

- अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकि के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक वशिष एजेंसी है।
- इसे संचार नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुवधि के लिये वर्ष 1865 में स्थापति कयिा गया। इसका मुख्यालय जनिवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह की कक्षाओं को आवंटति करता है, तकनीकी मानकों को वकिसति करता है ताकि नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों को नरिबाध रूप से आपस में जोड़ा जा सके और दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदायों के लिये ICT तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास कयिा जाए।
- भारत को अगले 4 वर्षों की अवधि (2019-2022) के लिये पुनः अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) परिषद का सदस्य चुना गया है। भारत वर्ष 1952 से इसका एक नियमति सदस्य बना हुआ है।

## इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC)

- ICC दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ज़मिमेदार व्यावसायिक आचरण को बढावा देने के लिये काम कर रहा है।
- यह वर्ष 1923 से व्यापार और निवेश का समर्थन करने के लिये अंतरराष्ट्रीय वाणजियकि और व्यावसायिक विवादों में कठनिाइयों को हल करने में मदद कर रहा है।
- ICC का मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है।

## स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/devas-antrix-deal>